वर्ष-2, अंक 3, मार्च 2019

राज भवन संवाद

राज भवन, बिहार की मासिक पत्रिका

विशेष आकर्षण

- बिहार की शैक्षिक विरासत अत्यन्त समृद्ध रही है-राज्यपाल
- राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित 'उद्यान प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया
- सभी विश्वविद्यालयों में शुरु होंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स-राज्यपाल

राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है

"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।" –अर्थात् शरीर ही धर्म–पालन का प्रथम साधन है। वस्तुतः स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। स्वस्थ आत्मा के लक्षण हैं– साहस, शौर्य, धीरता, स्थिरता, शांति, प्रसन्नता एवं असंकीर्णता। इन गुणों की बदौलत ही मनुष्य अपना आत्मिक अभ्युदय कर पाता है, आध्यात्मिक विकास कर पाता है। अतएव स्पष्ट है, धर्म–साधना एवं आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। एक कहावत है कि "एक तंदुरूस्ती हजार नियामतें।' –अर्थात्, अगर शरीर तन्दुरूस्त है, भला–चंगा है तो इंसान हजारों संकटों का सामना कर सकता है।

वस्तुतः इस धरती पर पीड़ित मानवता की सेवा से अधिक बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में लिखा है कि– "सेवा धर्म कठिन जग जाना।" उन्होंने परोपकार और परहित सेवा की भावना को सबसे बड़ा उत्कृष्ट धर्म बताते हुए कहा है कि– "परहित सरिस धर्म नहिं भाई / परपीड़ा सम नहिं अधमाई।।"

–पीड़ित मानवता को स्वस्थ, आरोग्य एवं आयुष्मान बनाना चिकित्सकों का परम धर्म है। चिकित्सक धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में भी चिकित्सकों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा–पद्धति विश्व को भारत की अनमोल देन है। आधुनिक चिकित्सा–पद्धतियों के विकास में भी हमारे ऋषियों–महर्षियों का अनुपम योगदान रहा है।

सुश्रुत आधुनिक चिकित्सा पद्धति में 'सर्जरी विधा के जनक' माने जाते हैं। महर्षि चरक, च्यवन, नागार्जुन आदि अनेक प्राचीन ऋषियों ने चिकित्साशास्त्र में विश्व को अपने कई शोधों और अवदानों के जरिये उपकृत किया है।

भारत सरकार एवं बिहार सरकार दोनों स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के विकास के लिए दृढ़संकल्पित हैं। भारत सरकार की 'आयुष्मान भारत योजना' तो जैसे गरीब रोगियों के लिए एक वरदान के रूप में ही सामने आई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार देश के 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रूपये की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य में उपलब्ध उन्नत स्वास्थ्य–सेवाओं का ही यह परिणाम है कि बिहार का मातृ–मृत्यु–अनुपात, जो सन 2005–06 में 371 था, वह वर्तमान में घटकर 165 रह गया है। इसी तरह शिशु मृत्यु–दर भी 2005–06 की तुलना में 61 से घटकर अब 38 हो गयी है। बच्चों का प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण 18 प्रतिशत से बढ़कर आज 84 प्रतिशत हो गया है, जिसे शत–प्रतिशत किया जाना बेहद आवश्यक है।

राजधानी पटना में 'एम्स' की स्थापना हो चुकी है। आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ एवं पी॰एम॰सी॰एच॰ सहित राज्य के पुराने सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों को आधुनिकीकृत एवं पूरी तरह विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दो नये मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया है। राज्य सरकार विभिन्न जिलों में 11 नये मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। मुझे विश्वास है, इन सब चिकित्सा–सुविधाओं के विकास के बाद, असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को भी अब राज्य से बाहर इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो इलाज के नाम पर बिहार के बाहर चली जानेवाली धन–राशि बिहार के विकास में ही लगेगी। फलतः बिहार आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होगा तथा विकसित राज्यों की श्रेणी में शीघ्र ही शुमार हो जाएगा।

(बक्सर में आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ मेला में बोलते हुए राज्यपाल (23 फरवरी 2019)

महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के मार्ग-दर्शन में राजभवन द्वारा निरंतर उच्च शिक्षा के विकास हेतु नयी पहलें की जा रही हैं, साथ ही राजभवन की गतिविधियों को लोकान्मुखी बनाते हुए अपनी जनतांत्रिक अस्मिता, मर्यादा और दायित्व-भावना का भी सतत् निर्वहन किया जा रहा है।

अपने संकल्पों के अनुरूप राज्य में उच्च शिक्षा के विकास-प्रयासों को तेज करने निमित्त उच्च शिक्षा का 'ब्लू प्रिन्ट' तैयार करने के लिए ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का एक राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम राजभवन में विगत 4-5 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हुआ। पटना विश्वविद्यालय के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकास-प्रयासों को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने की उनकी योजना दूरगामी प्रभाव वाली होगी। मतलब साफ है, इस परिसंवाद में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा व्यक्त सुझावों का सूत्रण करते हुए जो कार्य-योजनाएँ तैयार होंगी, उनमें कुछ तात्कालिक लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से कार्यान्वित होंगी, कुछ मध्यकालिक उद्देश्यों को पूरा करनेवाली होंगी, जिनसे प्रगति को नयी दिशा मिलेगी और कुछ ऐसी विशिष्ट योजनाएँ होंगी, जिनके प्रभाव स्थायी और व्यापक होंगे। 'लांग-टर्म गोल' वाली ऐसी योजनाएँ चरणबद्ध रूप में लागू होंगी। विकास की इस 'रूपरेखा' में सभी विश्वविद्यालयों की स्थानीय आवश्यकताओं का भी समाहार हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालयों के भी मंतव्य प्राप्त किये जा रहे हैं। फरवरी के एक अन्य महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में 'उद्यान प्रदर्शनी' भी उल्लेखनीय है। ऑनलाईन आवेदन के आधार पर राजभवन में पहली बार इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आम दर्शकों को भी प्रवेश दिया गया था। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शों वाले कृषकों को पुरस्कृत भी किया गया। वस्तुत: महामहिम की यह एक अनूठी पहल थी, जिसका सबने स्वागत किया।

निकट भविष्य में शीघ्र ही 'नैक' एक्रेडिटेशन तथा विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के 'डिजिटाईजेशन' को लेकर राजभवन में कार्यशालाओं के आयोजन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

हमें विश्वास है, हम अपने सपनों को साकार करने हेतु मजबूत इरादों के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएँगे और सबके सहयोग और सद्भाव की बदौलत कामयाबी हासिल करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

सधन्यवाद,

(विवेक कुमार सिंह)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

वर्ष-2, अंक-3, मार्च 2019
प्रधान सम्पादक
विवेक कुमार सिंह

कार्यकारी सम्पादक
विनोद कुमार

सम्पादक मंडल
संजय कुमार
सुनील कुमार पाठक

सम्पादकीय पता: जन-सम्पर्क शाखा, राजभवन, पटना-22
ई मेल- pr.rajbhavan@gmail.com
दूरभाष- 0612-2786119

इस अंक में

- राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है
- बिहार की शैक्षिक विरासत अत्यन्त समृद्ध रही है–राज्यपाल
- बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंश
- एन.सी.सी. राष्ट्रीयता, अनुशासन और सद्भावना के लिए संकल्पित संगठन है–राज्यपाल
- राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित 'उद्यान प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया
- 'सशस्त्रा–सेना झंडा दिवस कोष' के लिए राजभवन से 11 लाख रूपये दिये जायेंगे
- राज्य में स्वास्थ्य–सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है–राज्यपाल
- 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना': किसानों की हित–रक्षा एवं सम्मान की योजना है–राज्यपाल
- राज्य के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमी आगे आयें–राज्यपाल
- सभी विश्वविद्यालयों में शुरु होंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स–राज्यपाल
- उच्च शिक्षा के विकास में सबके सहयोग की आवश्यकता है –राज्यपाल
- विश्वविद्यालय परिसर
- शिष्टाचार
- विविधा
- बिहार के राज्यपाल (परिचय)

बिहार की शैक्षिक विरासत अत्यन्त समृद्ध रही है–राज्यपाल

'बिहार में उच्च शिक्षा की रूपरेखा' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल

"बिहार की शैक्षिक विरासत अत्यन्त समृद्ध रही है। बिहार में नालन्दा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहाँ पूरी दुनियाँ के लोग शोधपरक शिक्षा के उद्देश्य से आते थे। आज आवश्यकता है कि पुनः बिहार का शैक्षिक उत्थान कर इसकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाये और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में यहाँ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को शामिल करा पाने में सफलता हासिल की जाये।"–उक्त उद्गार, महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने राजभवन के राजेन्द्र मंडप में पटना विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में आयोजित "बिहार में उच्च शिक्षा की रूपरेखा" (Blueprint of Higher Education in Bihar) विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किए।

सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अनुरूप भारतीय नागरिकों को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेवारियों को गंभीरतापूर्वक समझें। राज्यपाल ने कहा कि आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सिर्फ पक्के इरादों के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 'नैक ग्रेडिंग' के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसके रास्ते 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' बनने की ओर भी बढ़ा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि 'नैक प्रत्ययन' की तैयारी के लिए बिहार सरकार टोकन–राशि उपलब्ध करा रही है। पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता की जा रही है। सभी विश्वविद्यालयीय विभागों एवं कॉलेजों को शौचालयों और गर्ल्स कॉमन–रूम के निर्माण के लिए भी धन राशि उपलब्ध कराई गई है।

राज्यपाल ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय–परिवार के पितातुल्य प्रतिपालक होते हैं। उन्हें अपना दायित्व बखूबी समझना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कुलाधिपति के रूप में बेहतर और उत्कृष्ट कार्य करनेवाले कुलपतियों को सदैव मेरा संरक्षण मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि उनके कार्यकाल में पिछले दिनों उच्च शिक्षा के सुधार–प्रयासों को लेकर जो प्रयास हुए हैं, वे संतोषप्रद हैं परन्तु अब भी काफी लंबा सफर तय करना है।

राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक जरूरतों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने की जरूरत है, पाठ्यक्रम को भी आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि आज उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए अगर हम तैयार किये जानेवाले उच्च शिक्षा के 'रोड–मैप' के अनुरूप, तेजी से चरणबद्ध रूप में आगे बढ़ते रहें तो बिहार राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था विकसित राज्यों के अनुरूप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महर्षि सुश्रुत ने 'सर्जरी के जनक' के रूप में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ायी है। अगर हम दृढ़निश्चय के साथ उच्च शिक्षा के विकास में तत्पर बने रहें तो हमारे गौरवशाली अतीत की भाँति ही हमारा वर्तमान भी वैभवपूर्ण हो जाएगा।

उद्घाटन–सत्र में बिहार के शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा ने सतत विकास हेतु शिक्षा के महत्त्वपूर्ण योगदान की चर्चा की। उन्होंने शिक्षा को सामयिक एवं मूल्यपरक बनाने पर जोर दिया तथा उच्च शिक्षा में सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाने में सहयोग हेतु सभी शिक्षण संस्थानों से आग्रह किया। शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, देशभक्ति एवं मानवाधिकार आदि के प्रति संकल्पित उत्कृष्ट नागरिक तैयार करना शिक्षा का परम उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकों के समन्वित प्रयासों से शिक्षा का विकास संभव है। श्री वर्मा ने कहा कि आधारभूत संरचना विकास के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिये भी उच्च शिक्षा को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा के विकास में महामहिम राज्यपाल के मार्ग–दर्शन और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग की भी सराहना की।

कार्यक्रम में बोलते हुए डॉ॰ आर॰सी॰ सोबती, राज्यपाल के शिक्षा परामर्शी ने अपने सम्बोधन में कहा कि शिक्षा को स्वावलंबी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को वहन करने वाला होना चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के बीच परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की सलाह दी।

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय में कार्यरत संयुक्त सचिव डॉ॰ एन॰ सरवन कुमार ने उद्घाटन–सत्र को सम्बोधित करते हुए बिहार में सब के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को NAAC मूल्यांकन हेतु आगे आने का आग्रह किया, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त कर पायें।

कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने इस सेमिनार के औचित्य पर प्रकाश डाला तथा बिहार के उच्च शिक्षा को जीवन्त, उत्साही तथा प्रभावोत्पादक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में शिक्षण–संस्थानों को पाठ्यक्रमेतर सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों को भी समयानुसार संचालित करने की सलाह दी।

('बिहार में उच्च शिक्षा की रूपरेख विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते राज्यपाला' – 4 फरवरी 2019)

उच्च शिक्षा विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल को स्मृति–चिह्न भेंट करते पटना विश्वविद्यालय के कुलपति (4 फरवरी 2019)

इस सम्मेलन में लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा से जुड़े बिहार के शिक्षाविद् बड़ी संख्या में मौजूद दिखे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया था।

आज सम्मेलन के प्रथम दिन चार तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गये जिसमें प्रथम सत्र में उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल पर संयुक्त सचिव (भारत सरकार) डॉ॰ एन॰ सरवन कुमार तथा महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन के श्री अनुपम ने संबोधित किया।

'नैक' से जुड़े दूसरे तकनीकी सत्र को 'नैक' के चेयरमैन डॉ॰ वीरेन्द्र सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 'नैक' की तैयारी के क्रम में 'नैक' से संबंधित कार्यशाला के आयोजन में उनकी संस्था भरपूर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में 'नैक मूल्यांकन' की फ्रेमिंग अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

आज के तीसरे तकनीकी सत्र में अकादमिक एवं परीक्षा सुधार तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास विषय पर 'नैक बेंगलूरू' के डॉ॰ रमा कोडापल्ली तथा एन॰यू॰पी॰ई॰ के सलाहकार डॉ॰ के रामचन्द्रन ने भी अपने विचार व्यक्त किये। आज के चौथे और आखिरी तकनीकी सत्र में छात्र–गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्वों तथा पूर्ववर्त्ती छात्र एवं विश्वविद्यालय परिसंवाद विषय पर राजभवन के शैक्षिक परामर्शी डॉ॰ आर॰सी॰ सोबती ने विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम में स्वागत–भाषण पटना पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ रासबिहारी प्रसाद सिंह एवं धन्यवाद–ज्ञापन पटना विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ॰ डॉली सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में 'राजभवन संवाद' पत्रिका के अंग्रेजी भाषा के प्रवेशांक का भी लोकार्पण राज्यपाल ने किया।

राष्ट्रीय सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन कुल 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों ने अपने विचार व्यक्त किये।

सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित प्रथम सत्र का विषय था –"National Institute Ranking Framework Related Issues and Industry Academia Interface – ('NIRF' से जुड़े मुद्दे एवं औद्योगिक शैक्षिक परिसंवाद")। इस सत्र के अन्तर्गत उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों को संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में लाने पर वक्ताओं द्वारा जोर दिया गया। इस सत्र में उच्च शिक्षा के निदेशक (EY) डॉ॰ सुचीन्द्र कुमार, श्री गौरव सिंह एवं पटना विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रो॰ डॉली सिन्हा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रो॰ डॉली सिन्हा ने अपने संभाषण के दौरान शिक्षण, प्रशिक्षण एवं संसाधनों को स्पष्ट करते हुए शोध एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने की वकालत की। वक्ताओं ने बताया कि 'NIRF' में सूचीबद्ध होने के लिए 'NAAC' से प्रत्ययन आवश्यक नहीं है।

दूसरे तकनीकी सत्र में "Issue of Quality and Relevance, Research, Improvement and Funding Agencies" (गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता से जुड़े मुद्दे –शोध, विकास तथा वित्त पोषण करनेवाली एजेन्सियाँ) –विषय पर व्यापक रूप से चर्चा हुई, जिसमें अम्बेदकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रो॰ श्याम मेनन, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ॰ अशोक कुमार घोष तथा टी॰पी॰एस॰ कॉलेज की डॉ॰ तनुजा ने संबोधित किया।

सत्र को संबोधित करते हुए प्रो॰ मेनन ने कहा कि शिक्षा में मैलिकता बहुत जरूरी है तथा इसके लिए बुनियादी ढ़ाँचे में सुधार भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभिन्न फन्डिंग एजेन्सियों से राशियाँ उपलब्ध हो रही हैं, जिन्हें प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है।

तीसरा तकनीकी सत्र पुस्तकालय सुविधाओं पर केन्द्रित था, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ॰ राजकुमार ने संबोधित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेजों में पुस्तकालय की अवधि सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक तथा विश्वविद्यालयों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने पुस्तकालयों को 'N-'LIST' से जुड़ने पर बल दिया तथा 'E-Granthalay' 'Koha' तथा 'New Genlib' –जैसे सॉफ्टवेयरों के माध्यम से पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया। इस सत्र में डॉ॰ अशोक कुमार झा ने शोधकार्यों में 'साहित्यिक चोरी' (Plagiarism) को रोकने तथा लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन पर बल दिया।

चौथे तकनीकी सत्र में (Extra Curriculum Activities, Sports and Cultural Activities) (पाठ्यक्रमेतर गतिविधियाँ – खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ") विषय पर केन्द्रित सत्र में राज्य के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के खेल निदेशक डॉ॰ संजय सिन्हा ने स्टेडियम निर्माण एवं राज्य सरकार की खेलकूद से जुड़ी कई योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई सरकारी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया, जिन्हें विश्वविद्यालय कार्यान्वित करा सकते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास पर पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो॰ शंकर आशीष दत्त ने प्रकाश डाला।

सम्मेलन में 'Role of Private Universities in the Development of Higher Education in Bihar' विषयक सत्र को एमिटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ टी॰आर॰ वेंकटेश ने संबोधित किया। उन्होंने राज्य में यथासंभव अधिक संख्या में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की वकालत की ताकि उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

सम्मेलन के एक सत्र में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर॰के॰ महाजन ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी शीघ्र दूर हो जाएगी। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं गुणवत्तावर्द्धन की भी आवश्यकता बतायी। कार्यक्रम को सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री राहुल सिंह ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम के समापन–सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा के ब्लूप्रिंट तैयार करने की दिशा में इस राष्ट्रीय सम्मेलन की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि काफी प्रभावोत्पादक एवं सारगर्भित व्यावहारिक सुझाव वक्ताओं ने दिए हैं। धन्यवाद–ज्ञापन पटना विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल मनोज मिश्रा ने किया।

बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंश

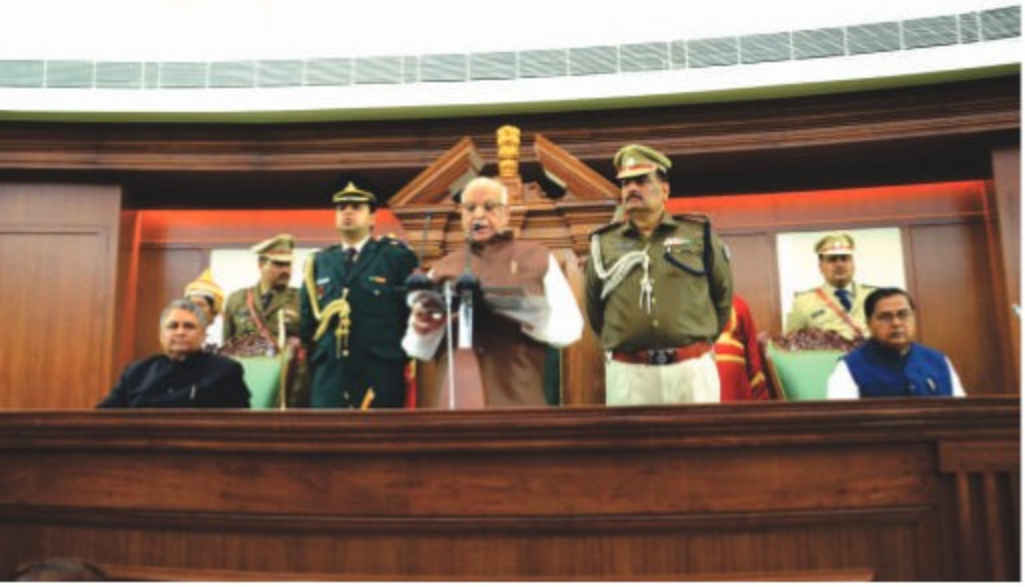

विधानमंडल के समवेत अधिवेशन को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल श्री लाला जी टंडन– 11 फरवरी 2019

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में आपको वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। राज्य सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथा–पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाएँ यथा–सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय की रूप–रेखा तैयार की तथा उन्हें सुशासन के कार्यक्रम में शामिल किया।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की रही है। प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को वर्ष 2018 के सुप्रतिष्ठित ''कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड'' तथा ''स्कॉच अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस'' से सम्मानित किया गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किये गये आंकड़ों में त्वरित आकलन के आधार पर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2017–18 में राज्य की विकास दर 11.3 प्रतिशत रही है। यह विकास दर देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रही है राज्य में 'महिला सशक्तीकरण नीति लागू की गयी है। महिला सशक्तीकरण हेतु सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के निर्वाचन तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब–इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार के निश्चय 'आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार' के तहत् राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य की गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के समेकित विकास, बचत को बढ़ावा देने, संस्था और क्षमता का निर्माण करने एवं वित्तीय समावेशन के लिए राज्य में जीविका कार्यक्रम लागू है। जीविका के तहत् अब तक 8.26 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा इससे 95.63 लाख परिवार जुड़े हैं। राज्य में बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पर आधारित ''मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना'' आरंभ की गई है।

'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' निश्चय के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में पाँच नये मेडिकल कॉलेज तथा प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान तथा प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ए.एन.एम. संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है। राज्य में उच्च शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से तीन नये पूर्णिया, पाटलिपुत्र एवं मुंगेर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा में विकास हेतु सभी विश्वविद्यालयों में 'शैक्षणिक कैलेण्डर' लागू किये गये हैं।

विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक एवं खोलकूद की अन्तरविश्वविद्यालीय प्रतियोगिताओं 'तरंग' एवं 'एकलव्य' को पुनर्जीवित कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक सकारात्मक शैक्षणिक–सांस्कृतिक वातावरण के विकास हेतु इस वर्ष 'चांसलर अवार्ड' विभिन्न प्रक्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवालों को प्रदान किये जाएगे। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा योजनाएँ संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना एवं सामाजिक सौहार्द्र का जो माहौल है, उसे कायम रखना है। राज्य सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास पर आप सार्थक चर्चा करेंगे जो राज्य के विकास में सहायक होगा।

।। जय हिन्द ।।

एन०सी०सी० राष्ट्रीयता, अनुशासन और सद्भावना के लिए संकल्पित संगठन है–राज्यपाल

(एन.सी.सी. के राजभवन में आयोजित एट होम समारोह में राज्यपाल – 7 फरवरी 2019)

"भारत में जिन उद्देश्यों को लेकर एन॰सी॰सी॰ की स्थापना हुई थी, यह संगठन उन उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तत्परता, गंभीरता और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ रहा है।" उक्त उद्‌गार, महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में भाग लेकर लौटे बिहार–झारखंड के एन॰सी॰सी॰ कैडेट्स के प्रोत्साहन में राजभवन, पटना में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये।

राज्यपाल ने कहा कि एन॰सी॰सी॰ की स्थापना का उद्देश्य था कि हम अपने देश में ऐसे युवाओं को तैयार करें, जो ऊर्जावान हों, तेजस्वी और ओजस्वी हों, पूर्ण अनुशासित हों, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के प्रति पूरी तरह समर्पित और गंभीर हों तथा देश के विकास के प्रति पूरी तरह सचेष्ट और प्रतिबद्ध हों।

श्री टंडन ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि एन॰सी॰सी॰ के माध्यम से आज ऐसे लाखों युवा हमारे देश में तैयार हो रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, साझी सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और प्रतिबद्ध हैं।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सपनों को साकार करने का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत दुनियाँ के सर्वोत्कृष्ट लोकतांत्रिक गणराज्यों में से एक है। भारतीय संविधान दुनियाँ के बेहतरीन संविधानों मे से एक है। इसकी 'प्रस्तावना' को ही अगर अपने जीवन में शिरोधार्य बना लिया जाये तो इस महान देश का एक आदर्श नागरिक बना जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि एन॰सी॰सी॰ के माध्यम से सामूहिकता, सामाजिकता और जीवन में सामंजस्य की भी शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक हितों के कार्य –यथा –रक्तदान शिविरों का आयोजन, साक्षरता अभियान, दहेज एवं नशा–उन्मूलन अभियान, कन्या–भ्रूण हत्या आदि के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य एन॰सी॰सी॰ तत्परतापूर्वक करती है। वृक्षारोपण, रक्तदान शिविरों का आयोजन, आपदा–प्रबंधन, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों में भी इसकी सहभागिता सराहनीय रहती है।

इस एट–होम समारोह में राज्यपाल श्री टंडन ने सर्वोत्तम कैडेट्स के रूप में –एफ॰सी॰शुभम बादल, एल॰/सी॰पी॰एल॰ मनु सिंह एवं कैडेट अस्मिता सिंह को मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान किया। बेस्ट लाईन एरिया ट्रॉफी कंटिजेन्ट कमान्डर कर्नल वीरेन्द्र सिंह को, जबकि बेस्ट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन डाइरेक्ट्रिएट की ट्रॉफी एन॰सी॰सी॰ बिहार–झारखंड उप महानिदेशक ब्रिगेडियर तुषार मिश्र को राज्यपाल द्वारा प्रदान की गई।

कार्यक्रम में वायुसेना के विमानों, हेलीकॉप्टर एवं समुद्री जहाजों के कई प्रदर्श–कैडेटों के द्वारा प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गये थे; जिनमें मिराज–2000 (वज्र), बोईंग–737 एवं हेलीकॉप्टर–बेल–206 तथा समुद्री जहाज INS-TABAR, INS KOCHI एवं कोलम्बस के प्रदर्शों को राज्यपाल ने अवलोकित किया।

कार्यक्रम में कैडेटों द्वारा देशभक्तिपूर्ण समूहगान एवं बिहार व झारखंड की लोक संस्कृति, संगीत–नृत्य–कलाओं आदि से जुड़े कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गये, जिसकी सबने प्रशंसा की।

कार्यक्रम में स्वागत–भाषण पटना ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार द्वारा किया गया।

समारोह में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ रास बिहारी प्रसाद सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल ए॰के॰ चौधरी (पी॰वी॰एस॰एम॰, ए॰वी॰एस॰एम॰, एस॰एम॰) सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर राजीवन लोचन पात्रो, ब्रिगेडियर सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव श्री विजय कुमार, सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक कर्नल दिलीप प्रसाद, राज्यपाल सचिवालय एवं राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारीगण, सैन्य एवं एन॰सी॰सी॰ के अधिकारीगण, कई कॉलेजों के प्राचार्यगण आदि उपस्थित थे।

(एन.सी.सी. एट होम समारोह में महामहिम राज्यपाल – 7 फरवरी 2019)

राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित 'उद्यान प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया

(उद्यान प्रदर्शनी में प्रदर्शों का अवलोकन करते हुए राज्यपाल– 14 फरवरी 2019)

''राज्य में कृषि के विविधीकरण तथा इसके अनुषंगी प्रक्षेत्रों के विकास की भी आवश्यकता है। खाद्यान्न–उत्पादन के साथ–साथ फल, फूल, सब्जी, सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन के जरिये भी किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो सकता है।''–उक्त बातें, महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन ने राजभवन के राजेन्द्र मंडप में आयोजित 'राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी' का उद्घाटन करते हुए कही।

राज्यपाल ने कहा कि राजभवन, पटना को भी फल, फूल, सब्जी, सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती के मामलों में एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से उद्यान–प्रदर्शनी आयोजन की नई शुरूआत हो चुकी है और अगले वर्ष से यह प्रदर्शनी और अधिक बड़े पैमाने पर 4–5 दिनों के लिए आयोजित होगी, ताकि अधिकाधिक लोग इसका अवलोकन कर सकें और किसानों की प्रतिभागिता में भी विस्तार हो।

राज्यपाल कहा कि राजभवन परिसर में विभिन्न नक्षत्र–ग्रहों के अनुसार पौधे लगाकर ''नक्षत्र वाटिका'' एवं विभिन्न प्रजाति के कमल लगाते हुए ''कमल वाटिका'' भी विकसित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सिन्दूर, रूद्राक्ष, बरगद, पीपल, पाकड़ आदि के पौधे भी लगाये जाएँगे, जिनसे पर्यावरण शुद्धीकरण होता है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण–संतुलन, पोषण, स्वास्थ्य और आनंद आदि की दृष्टि से भी पौधे लगाये जाने चाहिए।

श्री टंडन ने कहा कि रासायनिक खादों की जगह आज जैविक खादों के उपयोग का प्रचलन बढ़ रहा है। उन्होंने 'गो–पालन' की भी अपील करते हुए कहा कि एक गाय पालने से 10 एकड़ भूमि के लिए जैविक खाद की प्राप्ति हो जाती है तथा दूध–दही मिठाई जैसी खाद्य–सामग्रियाँ भी मिल जाती हैं।

राज्यपाल ने कहा कि 'जीरो बजट' कृषि का मॉडल भी आज देश में तैयार हो गया है, जिससे जैविक खेती को पर्याप्त बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने खस, लेमनग्रास (ज्वरांकुश) आदि सुगंधित पौधों के जरिये भी लाखों की आमदनी होने की बात करते हुए कहा कि किसानों को खाद्यान्न–उत्पादन के अलावा सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री टंडन ने स्ट्राबेरी, मशरूम आदि की खेती की बिहार में बड़े पैमाने पर हो रही शुरूआत की प्रशंसा की और कहा कि इससे किसानों की माली हालत में भी सुधार होगा और राज्य का भी तेजी से विकास होगा।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा उद्यान निदेशालय के माध्यम से राजभवन में आज आयोजित 'उद्यान प्रदर्शनी' में पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से आये सैकड़ों प्रगतिशील कृषकों आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ॰ अजय कुमार सिंह ने बताया कि 'उद्यान प्रदर्शनी' में कुल 521 प्रदर्शों को शामिल किया गया था, जिसमें फलों के 84, फूलों के 92 तथा सुगंधित एवं औषधीय पौधों एवं अन्य के कुल 110 प्रदर्श शामिल थे। प्रदर्शनी कुल 7 समूहों –सब्जी, फल, पत्तेदार पौधे (गमलों में) मौसमी फूल, मौसमी फूल (डंठल सहित), सुगंधित एवं औषधीय पौधे तथा मालियों के लिए गुलदस्ता बनाने, बटन होल, माला आदि तैयार करने –से जुड़े प्रदर्श शामिल किए गये थे।

प्रदर्शनी में लगभग 80 प्रदर्शों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। प्रथम पुरस्कार के रूप में 3000/–रू॰, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 2000/– एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 1000/– के पुरस्कार प्रदान किये गये। ऑर्नामेंटल कैबेज, गुड़हल, डहेलिया, पैन्जी, पिटूनिया, गुलाब, बेल एवं नींबू प्रदर्श के प्रथम पुरस्कार राजभवन उद्यान को प्राप्त हुए, जबकि राकेश कांत को अफ्रीकन गेन्दा, रमाकांत को फ्रेंच गेंदा, एस॰के॰ सिंह को डहेलिया, संजय चौधरी एवं गुलाब मेहता को केला, महेश प्रसाद सिंह को बेर, प्रीतम कुमार को पपीता, मृत्युंजय कुमार सिंह को अमरूद, वृजकिशोर प्रसाद महतो को स्ट्राबेरी, रघुनंदन पोद्दार को फूलगोभी, नागेन्द्र सिंह को बन्दगोभी, राजेश को ब्रोकली, मृत्युंज को माला–निर्माण एवं गाजर, राघवशरण प्रसाद सिंह को टमाटर, शशिभूषण सिंह को सेम, अजय कुमार प्रसाद को हल्दी, नकुल सिंह को मिर्च, मृत्युंजय सिंह को शिमला मिर्च, संतोष कुमार शर्मा को बैगन तथा संजय कुमार सिंह को ओल के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गये।

उद्यान प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, उद्यान निदेशक श्री नंद कुमार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कुलपति डॉ॰ अजय कुमार सिंह सहित राज्यपाल सचिवालय, कृषि विभाग तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि सलाहकार आदि भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में लगभग 400 किसानों ने भाग लिया, जबकि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के जरिये लगभग 350 दर्शनार्थियों ने भी इस दो दिवसीय 'उद्यान प्रदर्शनी' का अवलोकन राजभवन पहुँचकर किया।

(उद्यान प्रदर्शनी के उद्घाटन–समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल– 14 फरवरी 2019)

'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' के लिए राजभवन से 11 लाख रूपये दिये जायेंगे

(सशस्त्र सेना झंडा दिवस सामारोह में बोलते हुए राज्यपाल– 26 फरवरी 2019)

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने की अध्यक्षता में 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस समिति' की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक राजभवन में सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि सैनिकों के कल्याण की योजनाओं की सतत् सम्यक् समीक्षा की जानी चाहिए, साथ ही 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' में राशि–संग्रहण को गति प्रदान किया जाना जरूरी है।

राज्यपाल श्री टंडन ने 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' के लिए राजभवन, बिहार, पटना की तरफ से 11 लाख रूपये दिये जाने की भी घोषणा की तथा कहा कि सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी–गैर सरकारी संगठनों/विभागों, शिक्षण–संस्थाओं आदि को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उक्त कोष में राशि जमा करनी चाहिए।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि भारत की वीरता, राजनीतिक नेतृत्व की मजबूती, कार्य–कुशलता और नागरिकों की देशभक्ति को पूरा विश्व पूरे सम्मान के साथ आज देख रहा है। देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा में सदैव तत्पर रहनेवाले सैनिकों के कल्याण के लिए अर्थ–दान का अगर सौभाग्य हमें मिलता है तो यह हमारे लिए अत्यन्त गौरव की बात है। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सभी सरकारी विभागाध्यक्षों, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षण–संस्थाओं आदि को सैनिक कल्याण के लिए धन–संग्रह करने हेतु अभिप्रेरित करने का अनुरोध किया।

बैठक के दौरान राज्यपाल श्री टंडन ने वर्ष 2016–17 (7 दिसम्बर, 2016 से 6 दिसम्बर, 2017 की अवधि) तथा वर्ष 2017–18 (7 दिसम्बर, 2017 से 6 दिसम्बर, 2018 की अवधि) के बीच सर्वोच्च संग्रह करनेवाले प्रमंडल, विश्वविद्यालय, जिला, महाविद्यालय एवं सरकारी विभाग/संस्थान/उपक्रम आदि को राज्यपाल ने ट्रॉफी भी प्रदान किया।

बैठक में राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय एवं एन.सी.सी. के ए.डी.जी. ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, कुलपति, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी आदि उपस्थित थे।

राज्य में स्वास्थ्य–सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है–राज्यपाल

"राज्य में स्वास्थ्य–सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। आज न संसाधनों की कमी है, न दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव पूरे देश का नेतृत्व आज एक दूरदर्शी एवं सशक्त व्यक्तित्व के हाथों में है। नयी कल्याणकारी नीतियाँ भी बन रही हैं और उनका जनहित में तेजी से कार्यान्वयन भी हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। स्वास्थ्य–सुविधाओं या आर्थिक विपन्नता के कारण आज किसी का जीवन खतरे में नहीं पड़ सकता। 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाएँ गरीब और अभिवंचित वर्ग तक स्वास्थ्य–सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं।" –उक्त वक्तव्य; महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन ने आज इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान के '5वें दीक्षांत समारोह' को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा जगत् में भी भारत की विरासत काफी समृद्ध रही है। उन्होंने कहा कि महर्षि चरक, सुश्रूत आदि की सेवाएँ एवं ग्रंथ विश्व चिकित्सा जगत् को भारत का अनमोल अवदान हैं। राज्यपाल ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के डिग्री प्राप्तकर्त्ताओं में छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह तेजी से बदल रहे भारत की नयी तस्वीर है, जहाँ महिला सशक्तीकरण की अवधारणा तेजी से फलवती हो रही है।

दीक्षांत–समारोह में पहुँचने के पूर्व राज्यपाल ने आई.जी.आई.एम.एस. के नवनिर्मित विस्तारित नर्सिंग कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल ने 'वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका' तथा 'दूरभाष निर्देशिका' को भी लोकार्पित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि राज्य में विगत एक वर्ष में दर्जन भर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि कभी भी आर्थिक संसाधनों की कमी आई.जी.आई.एम.एस. के विकास में आड़े नहीं आएगी।

समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

समारोह में आई.जी.आई.एम.एस. के निदेशक डॉ. एन.आर. विश्वास ने स्वागत–भाषण एवं संस्था का प्रगति–प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 138 मेडिकल छात्र–छात्राओं को पदक, प्रमाण–पत्र एवं डिग्रियाँ प्रदान की गईं। समारोह में आई.जी.आई.एम.एस. के डीन प्रो. एस. के शाही, डीन (परीक्षा) प्रो. के.एच. राघवेन्द्र, रजिस्ट्रार डॉ. संगीता पंकज आदि भी उपस्थित थे।

(आई.जी.आई.एम.एस. पटना के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल को स्मृति–चिह्न समर्पित करते हुए संस्थान के निदेशक– 14 फरवरी 2019)

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'

किसानों की हित-रक्षा एवं सम्मान की योजना है-राज्यपाल

(प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ समरोह में राज्यपाल- 24 फरवरी 2019)

"केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों की हित-रक्षा में पूरी तरह तत्पर है। भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' किसानों का सम्मान बढ़ानेवाली योजना है, यह उनपर सरकार का कोई एहसान नहीं।" -उक्त उद्‌गार, महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) के सभागार में आयोजित 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के राज्य में शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

राज्यपाल ने कहा कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के कार्यान्वयन में प्रक्रियागत सहजता बरती गई है तथा इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि बिचौलियों की वजह इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं पनप पाए। राज्यपाल ने कहा कि आज देश के नेतृत्व ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर अभियान छेड़ रखा है। आज यह स्थिति नहीं है कि ऊपर से चलनेवाली सहायता-राशि नीचे लाभुकों तक पहुँचने में बिचौलियों के दुराचरण के कारण अत्यल्प हो जाए। आज भ्रष्टाचारियों की गर्दन पकड़ में है और वे गरीबों तक कल्याणकारी योजनाओं की राशि पहुँच पाने में बाधक नहीं हो पा रहे। राज्यपाल ने कहा कि आज ही बटन दबाते डिजिटली लाभुक किसानों के खाते में डिजिटली दो हजार रूपये की सम्मान राशि स्वतः अंतरिम होकर आ जाएगी। किसानों को इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।

राज्यपाल ने कहा कि आज सीमा पर तनाव के बावजूद विकास-कार्यों को बाधित नहीं होने दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार विकास-योजनाओं का शिलान्यास/उद्‌घाटन शुभारंभ कर रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि स्वाभिमान की रक्षा में तत्पर रहते हुए हम विकास के पथ पर भी सतत् आगे बढ़ते रहेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि आज शुरू हो रही सम्मान योजना की बदौलत लघु एवं सीमांत किसान अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब महाजनों के चंगुल में फँसने से बच सकेंगे।

कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री डॉ॰ प्रेम कुमार ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कृषि-योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। कार्यक्रम में स्वागत-भाषण कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद-ज्ञापन कृषि निदेशक श्री आदेश तितरमारे ने किया।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर (उ॰प्र॰) में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उक्त योजना का शुभारंभ किया।

राज्य के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमी आगे आयें-राज्यपाल

"राज्य के उद्यमियों को नये अनुकूल वातावरण में बिहार के औद्योगिक विकास हेतु ठोस पहल करनी चाहिए। सरकारी प्रयासों से ही सिर्फ औद्योगिक विकास संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए राज्य के उद्यमियों को भी उत्साहपूर्वक चरणबद्ध रूप से प्रयास करने होंगे।"-उक्त उद्‌गार, महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के सभागार में राज्य के उद्यमियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

इसके पूर्व राज्यपाल श्री टंडन ने बी॰सी॰सी॰आई॰ परिसर में 'उद्यमिता (कौशल विकास) भवन' का उद्‌घाटन महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद के साथ किया। समारोह में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि बिहार की विकास-दर पूरे देश में सर्वाधिक है और यह राष्ट्रीय विकास-दर से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में विकास के लिए समुचित वातावरण बन गया है। भारत सरकार के प्रयासों से सबको पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल रही हैं, रहने को घर मिल रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, भोजन को खाद्यान्न मिल रहे हैं तथा रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध हैं। राज्यपाल ने कहा कि अगर गरीब अल्पशिक्षित युवा और महिलाएँ थोड़ी भी हूनरमंद हो जाती हैं, तो उनके लिए रोजगार मिलना आसान हो जाएगा। श्री टंडन ने कहा कि कौशल-विकास के जरिये समाज के अभिवंचित वर्ग को भी रोजगार मुहैय्या कराते हुए उनका आर्थिक सशक्तीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर-प्रशिक्षण के अलावा अन्य छोटे-छोटे हूनर भी अगर कमजोर वर्ग की महिलाएँ प्राप्त कर लेती हैं तो उनका भी पूरा आर्थिक सशक्तीकरण संभव है।

(बी.सी.सी.आई. के समारोह का उद्‌घाटन करते राज्यपाल- 2 फरवरी 2019)

कार्यक्रम में राज्यपाल ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करनेवाले लगभग दर्जन भर उद्यमियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी गरीब महिलाओं में प्रमाण-पत्र एवं सिलाई-मशीनों का भी वितरण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम का दौरा कर वहाँ के चेम्बर-प्रतिनिधियों से वार्त्ता की है एवं एक-दूसरे के विचारों और अनुभवों को साझा किया है।

कार्यक्रम में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सभी विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स–राज्यपाल

(टी. एम. बी. विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल– 12 फरवरी 2019)

बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू होंगे। इससे स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें यूनिवर्सिटी से निकलते ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही सूबे के विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी शुरू होगा। ये बातें बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहीं।

उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा के विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियां आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार करने को कहा है। विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कुछ ठोस और सार्थक कदम भी पिछले वर्ष हमने उठाए हैं। उसके सार्थक और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। एकेडमिक एवं एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुरूप समय पर नामांकन, परीक्षा आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन तथा डिग्री वितरण के लिए दीक्षांत समारोह के आयोजन किए जा रहे हैं।

राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (यूएमईएस) इस वर्ष से लागू होने जा रहा है। इसका फायदा छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा। वहीं सभी यूनिवर्सिटी में जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने से उद्देश्य से विशेष अभियान चलाए गए हैं। हर परिसर, हरा परिसर नामक पौधारोपण योजना के तहत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिसर में लाखों पौधे लगे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप दीक्षांत समारोह के लिए नई परिधान व्यवस्था कार्यान्वित कर दी गई है। इसका अवलोकन आज के समारोह में भी आप कर रहे हैं। यह बड़े हर्ष की बात है और मुझे भी खुशी है कि आज विश्वविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग आधी पाई जा रही है। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो दीक्षांत समारोह के दौरान 80 प्रतिशत तक स्वर्ण पदक छात्राएं हासिल कर रही हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी लगभग आधे स्वर्ण पदकों पर हमारी बेटियों की दावेदारी सफल रही है। विश्वविद्यालय बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। पूरे राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है। बिहार कुछ वर्षों में ही विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने में सफल हो जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य का विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। उम्मीद है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में और बेहतर कर विकास दर को और ऊंचा करेंगे और बिहार कुछ वर्षों में विकसित राज्यों की श्रेणी में जगह बना सकेगा। कुलाधिपति ने कहा कि चार और पांच फरवरी को राजभवन में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए दस सत्रों में सेमिनार हुआ था। इसमें आए विचारों और सुझावों पर अमल किया जाएगा, जिससे राज्य में शिक्षा के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। शिक्षा में सुधार से जुड़ी अगले पांच सालों के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। विवि में सुधार के अब तक के प्रयासों और निर्णयों की चर्चा करते हुए कुलाधिपति ने कहा कि विवि समाज के प्रति जवाबदेह बनें। उन्होंने छात्रों से कहा कि दीक्षांत दीक्षा का औपचारिक अंत है, यह शिक्षांत नहीं है क्योंकि शिक्षा जीवन भर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। साल के बाद छात्र जिस दुनिया में प्रवेश करेंगे वह बेहद चुनौतीपूर्ण है। ईमानदारी और लगन दिखाएंगे तो चुनौतियों पर जीत दर्ज करेंगे। प्रण लें कि भारत के उत्थान में अपना पूरा योगदान देंगे।

समारोह में आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. पुष्पक भट्टाचार्य ने दीक्षांत भाषण दिया। अतिथियों का स्वागत प्रभारी कुलपति प्रो. लीला चंद साहा और धन्यवाद ज्ञापन प्रतिकुलपति प्रो. रामयतन प्रसाद ने किया।

उच्च शिक्षा के विकास में सबके सहयोग की आवश्यकता है – राज्यपाल

बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विवि के 'दीक्षांत समारोह' में बेटियों का दबदबा रहा। विश्वविद्यालय की ओर से 37 छात्र–छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए। इनमें से तीस पर बेटियों ने ही कब्जा किया। एलएस कॉलेज मैदान में विवि के छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। उनकी इस उपलब्धि पर अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा कि 80 फीसदी बेटियों ने गोल्ड मेडल लिया है। यह बदलाव का बड़ा संकेत है। जिस समाज में बेटियों को जन्म लेने नहीं दिया जाता था। पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समाज की सोच एक नारे ने बदल दी। आज 'बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ' का नारा सफल हुआ। गोल्ड मेडल स्नातक, पीजी, बीएड व लॉ के 37 छात्र–छात्राओं को दिए गए।

राज्यपाल ने देश के मौजूदा हालात के बारे में कहा कि आज आपको तय करना है कि स्वाभिमान के साथ जीना है या अपमान के साथ। उन्होंने कहा कि आज युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन क्या इसकी शुरूआत हमने की है? कोई एकाध गलती करेगा तो हम क्षमा कर देंगे। लेकिन, लगातार क्षमा करना कायरता होगी और कायरता से बड़ी कोई त्रासदी नहीं है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के स्तर पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसी स्तर की शिक्षा पद्धति की जरूरत है। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक पूर्व सांसद प्रो. रामजी सिंह ने देश की वर्तमान स्थिति पर विचार रखें। उन्होंने पीस एजुकेशन को बढ़ावा देने की सलाह दी। नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने भी विचार रखें। नगर एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। दीक्षांत समारोह में छात्र–छात्राओं को सम्मान दिया जा रहा है। हमलेग इसके साक्षी बने रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सच में राज्यपाल के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में विकास का लगातार प्रयास हो रहा है। इसी प्रयास का नजीता है कि दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है।

कुलपति डॉ. अमरेंद्र नारायण यादव ने स्वागत भाषण में विवि की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि इस वक्त इस विवि में चार लाख छात्र पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वृहद विवि है। नेपाल व उत्तरप्रदेश के बॉर्डर तक यह फैला है। धन्यवाद ज्ञापन प्रोवीसी डॉ. आरके मंडल ने किया। कुलसचिव अजय कुमार राय ने दीक्षांत समारोह का प्रोसेस पढ़ा व मंच संचालन डॉ. ममता रानी ने किया। टॉपरों की घोषणा परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओपी रमण ने की।

(बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विवि के 'दीक्षांत समारोह' में महामहिम राज्यपाल– 27 फरवरी 2019)

विश्वविद्यालय परिसर

बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

'बीएनएमयू संवाद' का लोकार्पण

राजभवन संवाद की तर्ज पर जनवरी 2019 से बीएनएमयू संवाद का प्रकाशन किया जा रहा है। इसका प्रवेशांक दीक्षांत समारोह विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसका लोकार्पण करते हुए कुलपति डॉ. अवध किशोर राय ने कहा कि 'बीएनएमयू संवाद' विश्वविद्यालय का आइना बनेगा। यह पत्रिका प्रत्येक तीन माह पर नियमित रूप से प्रकाशित होगी। इसका अगला अंक अप्रैल में प्रकाशित होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रति कुलपति डॉ. फारूक अली ने की और संचालन पीआरओ डॉ. सुधांशु शेखर ने किया।

गाँधी प्रतिमा का अनावरण

बीएनएमयू साउथ कैम्पस में सामान्य शाखा के सामने वाले पार्क में महात्मा गाँधी की प्रतिमा लगाई गई है। 30 जनवरी को गाँधी शहादत दिवस के अवसर पर कुलपति डॉ. अवध किशोर राय ने प्रतिमा का अनावरण किया।

कुलपति ने कहा कि गाँधी ने दुनिया को सत्य एवं अहिंसा का रास्ता दिखाया है। इसी रास्ते पर चलकर देश–दुनिया का कल्याण हो सकता है। हमें गाँधी के सपनों की दुनिया बनानी है।

मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के भवन का शिलान्यास

मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के लिए आवंटित 5.04 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित भवनों की नींव बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा मीठापुर के शैक्षणिक परिसर में एक भव्य समारोह में 25/02/2019 को संध्या 04:30 बजे रखी गयी जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी और राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा भी उपस्थित थे। यह विश्वविद्यालय वैसे तो 1992 में स्थापित हुआ लेकिन इसका शैक्षणिक सत्रा 2008 में शुरू हुआ। अपना भवन नहीं रहने के कारण यह विश्वविद्यालय इधर उधर किराए के भवनों से काम करता रहा

और आगे नहीं बढ़ सका। अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधरभूत संरचना विकास निगम ;ठैम्क्ब्द्ध द्वारा इस विश्वविद्यालय का जो भवन बनाया जाना है वह आधुनिक एवं परम्परागत वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना होगा और अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा।

उल्लेखनीय है कि 22 दिसम्बर 2018 को बिहार के राज्यपाल सह–कुलाधिपति महामहिम श्री लाल जी टंडन ने विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में स्वयं तशरीफ लाकर फाजिल और स्नातकोत्तर छात्र–छात्राओं को अपने हाथों उपाधि और स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए भरी सभा में दिल से कामना व्यक्त की कि अगला दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के अपने भवन में हो।

शिलान्यास के इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. खालिद मिर्ज़ा ने इस बात का विश्वास दिलाया कि भवन बनते ही इसके प्रांगण में एक उत्कृष्ट विभाग ''डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएन्टल स्टाडीज़'' स्थापित होगा जिसमें अरबी, फारसी और इस्लामिक अध्ययन की तीन अलग–अलग विशिष्ट शाखायें स्थापित की जायेंगी जहाँ देश–विदेश के नामचीन स्कॉलर छात्र–छात्राओं को और शोधार्थियों को अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

नयी तालीम, प्रायोगिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा पर हुई कार्यशाला

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद् के सहयोग से 'नयी तालीम, प्रायोगिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा' पर शुक्रवार 08 फरवरी को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह ने की। सम्मानित अतिथि प्रति–कुलपति डॉ. जय गोपाल एवं विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष, छात्र कल्याण, प्रो0 रतन कुमार चौधरी, संकायाध्यक्ष (शिक्षा) प्रो0 अजीत कुमार सिंह, कुलसचिव कर्नल निशीथ कुमार राय, प्रभारी निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय डॉ. विजय कुमार थे। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद् की ओर से सहायक निदेशक डॉ॰ देवेन्द्र नाथ दास संसाधन पुरूष के रूप में उपस्थित रहे। अपने अध्यक्षीय भाषण में कुलपति प्रो0 सिंह ने कहा कि छात्र नन्हें पौधें के समान होते हैं और उन्हें पोषित करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। साथ ही शिक्षकों को हमेशा अपने ज्ञान का वर्द्धन करते रहना चाहिए तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि गांधी की नयी तालीम की प्रासंगिकता आज भी है और आज बिना कौशल के शिक्षा बेमानी होती जा रही है।

शिष्टाचार

(माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बिहार–यात्रा के दौरान पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते हुए महामहिम राज्यपाल दिनांक 17 फरवरी, 2019)

(उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन, दिनांक– 20 फरवरी, 2019)

विविधा

(महामहिम राज्यपाल व माननीय मुख्यमत्री ने राजभवन, बिहार पर केन्द्रित 'वार्षिक कैलेण्डर' लोकार्पित करते हुए
दिनांक 14 फरवरी, 2019)

(राजभवन में लगाये गये कुल नौ महापुरूषों के तैल–चित्रों को देखते महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री व अन्य,
दिनांक 14 फरवरी, 2019)

(गोपेश्वर महाविद्यालय, हथुआ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल एवं अन्य, दिनांक– 28 फरवरी, 2019)

(प्रयागराज में आयोजित कुंभ–2019 के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल– 13 फरवरी 2019)

बिहार के राज्यपाल

(स्वतंत्रता के बाद)

जयरामदास दौलतराम

15 अगस्त 1947 . 11 जनवरी 1948

वे एक स्वतंत्रता-सेनानी एवं राजनेता थे। उन्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत बिहार का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। भारत के केन्द्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने 1950 से 1956 तक असम के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान की।

माधव श्रीहरि अणे

12 जनवरी 1948 से जून 1952

वर्ष 1948 से 1952 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहने के उपरांत वे तृतीय लोकसभा (1962-1967) के सदस्य भी रहे। उन्हें 1968 में 'पद्मभूषण' से तथा मरणोपरांत 'साहित्य-अकादमी' पुरस्कार से वर्ष 1971 में सम्मानित किया गया। पटना के अणे मार्ग का नाम इनके नाम पर ही रखा गया है ।

राजेन्द्र मंडप, राजभवन, पटना की रात्रिकालीन छवि

मुद्रक : लेजर प्रिंटर्स, पटना 4, फोन : 9334116085
laserpatna@gmail.com